अश्विनी कुमार मिश्रा

बनाम

पी. मुनियाम बाबू और अन्य

अप्रैल 8,1999

[एस. सगीर अहमद और आर. पी. सेठी, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

धाराएँ 140,141,142,146,149,166,168,171,173-दुर्घटना के दावे के खिलाफ मुआवजा-अदालतों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड-कुछ अनुमान, कुछ काल्पनिक विचार और चोट की प्रकृति और गंभीरता के साथ कुछ मात्रा में सहानुभूति सभी प्रासंगिक हैं-लेकिन इन सभी मुद्दों को वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ देखा जाना चाहिए-अपीलकर्ता के साथ हुई दुर्घटना जिसमें वह स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हो गया- जीवन भर के लिए उसकी देखभाल करने के लिए स्थायी परिचारक की आवश्यता था। अभिनिर्धारित, अपीलकर्ता का अपने पिता की कंपनी में काम करते हुए 2000 रुपये की मासिक आय का दावा करना सही था रोजगार या आय को महत्वहीन दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की आभारा-उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मुआवजे की राशि को रु. से। 2,25,000 रु. से बढ़ाकर 5,00,000 तक कर दी गई।

दुर्घटना दावा-औपाचारिक रुप से नियोजित हुए बिना काम करने वाले व्यक्ति के लिए अपीलार्थी 23 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना का शिकार हो गया वह स्थायी रूप से अक्षम हो गया। दुर्घटना के समय अपने पिता की कंपनी के लिए काम कर रहा था-अपीलार्थी इस प्रकार प्रति माह 2000 रुपये कमाने का दावा कर रहा था। अभिनिर्धारित, दुर्घटना पीड़ित अदालत द्वारा मुआवजे की राशि की गणना के उद्देश्यों के लिए नियमित मासिक आय का दावा कर

सकता है-नुकसान का आकलन करने में कुछ अनुमान लगाना पड़ता है-अपीलार्थी के दावे को स्वीकार किया गया।

नुकसान का आकलन-एक मोटर वाहन दुर्घटना में अभिनिर्धारित न्यायालय अपनी राय को केवल अटकलों या कल्पनाओं पर आधारित नहीं कर सकता है हालांकि कुछ हद तक अनुमान अपरिहार्य है।

23 साल की उम्र में एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं और दुर्घटना के परिणामस्वरुप वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया। इसमें कोई विवाद नहीं था कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी अपने पिता की सहायता कर रहा था जो एक निर्माण कंपनी के मालिक थे। हालाँकि अपीलार्थी को औपचारिक रूप से कंपनी द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना के समय वह एक कंपनी के कर्मचारी के रूप में यात्रा कर रहा था। कंपनी से उसकी मासिक आय के रूप में 2000 रु. का भी दावा किया। न्यायाधिकरण ने एक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में 1,64,037 रुपये की राशि देने का फैसला किया बीमा कंपनी और अपीलार्थी दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिस ने मुआवजे को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ 2,25,000 रुपये तक बढ़ा दिया इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वह दुर्घटना के समय 2,000 रुपये की आय प्राप्त कर रहा था। और उसने उस हानि आय के बदले में उसे मुआवजा देने के लिए 55 का गुणक लागू करने के लिए प्रार्थना की जो उसके पास दुर्घटना के अभाव में अर्जित होगा जिसमें वह पूरी तरह से अक्षम हो गया हो। बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उसकी आय का कोई प्रमाण नहीं था और यह साबित नहीं हुआ कि वह अपने पिता का कर्मचारी था।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया 1.1. मुआवजे की राशि में कुछ अनुमान कुछ काल्पनिक विचार, कुछ मात्रा में विकालंगता की प्रकृति से जुड़ी सहानुभूति शामिल है लेकिन ऐसे सभी तत्वों को वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ देखने की आवश्यकता है। क्षति का आकलन करते समय, अदालत अपनी राय को केवल अटकलों या कल्पना पर आधारित नहीं कर सकती है, हालांकि कुछ हद तक अनुमान अपरिहार्य हैं। [502 - ए-बी]

आर. डी. हट्टंगडी **बनाम** *कीट नियंत्रण (भारत) प्रा. लिमिटेड और अन्य,* **[1995] 1 एससीसी 551, पर निर्भय किया गया।**

1.2. तत्काल मामले में, अपीलार्थी को चिकित्सा देखभाल पर किए गए खर्च के रूप में 94,037 रुपये विशेष आहार के लिए 20,000 रुपये और उपचार के दौरान परिचारक के लिए खर्च के रुप में मुआवजा दिया गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में लगी चोट और क्षति के कारण उसके स्थायी रुप से विकलांग हो जाने और लकवाग्रस्त हो जाने के कारण अपीलार्थी, जिसे स्वीकार किया गया है कि स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया है, को केवल 1,00,000 दिए गए है। अपीलार्थी ने अपने पिता के साथ काम करते समय प्रति माह 2000 रुपये की आय का दावा करने में सही था और 16 का गुणक लागू होने पर भी वह निराशा, हताशा और मानसिक तनाव के अलावा जीवन की उम्मीद के नुकसान के कारण 3,84,000 रुपये के दावे का हकदार है, विशेष रूप से जब उसे अपने शेष जीवन के दौरान अपनी देखभाल के लिए एक स्थायी परिचारक रखना पड़ता है। इस राशि को 1,14,000 रुपये की राशि में जोड़ने पर जिसके लिए अपीलार्थी को चिकित्सा देखभाल पर किए गए खर्च और उपचार की अवधि के दौरान दर्द और पीड़ा के लिए उचित रूप से हकदार ठहराया गया है, अपीलार्थी कुल 4,98,000 रुपये की राशि का हकदार है। जो मुकदमे की लागत सहित

5,00,000 तक है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था, उपरोक्त राशि प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा भुगतान करने योग्य है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2158/1999

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एम. ए. सं. 633/1994 के दिनांकित 31.3.98 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए गिरधर जी. उपाध्याय, सुश्री विनीता जी. उपाध्याय और आर. डी. उपाध्याय।

उत्तरदाताओं के लिए सुश्री संगीता कुमार।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सेठी, न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई।

उत्तरदाता को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि अपीलार्थी के पक्ष में मुआवजे की राशि को और क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी संख्या 3-न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अपीलार्थी दुर्घटना के समय कहीं भी कार्यरत था और उसकी आय के बारे में सबूत के अभाव में, मुआवजे की राशि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चुंकि अपीलार्थी ने 2,90,919.15 रुपये का दावा किया था और उसे ब्याज के साथ 2,25,000 रुपया का, मुआवजे दिये गये थे, इसलिए उसके लिए मुआवजा की राशि में वृद्धि का दावा करने का कोई औचित्य नहीं है।

वर्तमान अपील के भरने के लिए तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी, जिसकी आयु 23 वर्ष है, एक दुर्घटना में घायल हो गया था और उसे गंभीर चोटें आई थीं जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी

को नुकसान पहुंचा था। वह नीचे रह गया। उनका लगभग 90 दिनों तक इलाज किया और स्थायी रूप से विकलांग हो गए। उन्होंने मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के लिए वाहन के मालिक, चालक और बीमाकर्ता से 63,00,919.15 रुपये का दावा मांगा था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद इसे 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने मामले में दिए गए साक्ष्य की सराहना करते हुए कहा गया कि अपीलकर्ता निर्माण फर्म के एजेंट के रूप में यात्रा कर रहा था जब वह दुर्घटना का शिकार हुआ और उसे 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1,64,037 रुपये का मुआवजा दिया गया। अपीलार्थी और बीमा कंपनी दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी, जिन्हें आक्षेपित फैसले द्वारा निपटाया गया था जिसमें अपीलार्थी को मुआवजे के रुप में रुपये 2.25.000 देय मुआवजे के रूप में 10 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देय था न्यायाधिकरण द्वारा।

यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी/गुर्दे का कई बार ऑपरेशन हुआ और वह जीवन भर सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अमान्य हो गए। अपीलार्थी ने दावा किया था कि दुर्घटना के समय उसकी आय 2,000 रुपये प्रति माह जब वह 23 वर्ष के थे। उन्होंने आय के नुकसान के बदले में उन्हें मुआवजे देने के लिए 55 के गुणक को लागू करने के लिए प्रार्थना की थी, जो उन्होंने दुर्घटना के अभाव में अर्जित किया होता, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है वे पूरी तरह से अक्षम हो गए थे। बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उसकी आय का कोई प्रमाण नहीं है और वह साबित नहीं हुआ कि वह उस काम में अपने पिता का कर्मचारी था जहां दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग शुरू किया गया था। हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि दुर्घटना के समय, अपीलकर्ता आवासीय और गैर-आवासीय क्वार्टरों के सामने बड़े लगाने के नीवीनीकरण के लिए कैलाश नगर के टाउनशिप में जमा संख्या 40 में सुनीता कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य में अपने पिता

की सहायता कर रहा था, जो सी. सी. प्रदान कर रहा था। जब वह दुर्घटना का शिकार हुआ तो कैलाश नगर की परिसर की दीवारों के लिए चश्मे का कर सके, उन्होंने अपनी आय 2000 रुपये प्रति माह होने का दावा किया है। अपीलार्थी, एक युवक को अपने पिता की आय में योगदान देने और बढ़ाने के लिए विवादित नहीं किया जा सकता है। नुकसान का आकलन करते समय कुछ अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। आर. डी. हट्टंगडी बनाम में यह न्यायालय। मेसर्स पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। , [1995] 1 एस. सी. सी. 551 ने यह न्यायालय में अभिनिर्धारित किया थाः-

> "विस्तृत रुप से किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को देय मुआवजों की राशि तय करते समय, क्षति का आकलन आर्थिक क्षति और विशेष क्षति के रूप में, अलग-अलग आर्थिक क्षति वे हैं जिन्हें पीड़ित ने वास्तव में वहन किया है और जिनकी गणना धन के संदर्भ में की जा रही है; जबकि गैर-आर्थिक क्षति वे हैं जिनका गणना अंकगणितीय द्वारा मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। दो अवधारणाओं की सराहना करने के लिए आर्थिक क्षति में दावेदार द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैंः (i) चिकित्सा उपस्थिति;(ii) परीक्षण की तिथि तक लाभ अर्जित करने की हानि होती है। (iii) अन्य भौतिक क्षति। जहाँ तक गैर-आर्थिक क्षति का संबंध है, उनमें शामिल हो सकते हैंः (i) मानसिक और शारीरिक आघात, दर्द पीड़ा पहले से ही पीड़ित या भविष्य में पीड़ित होने की संभावना के लिए क्षति (ii) जीवन की सुविधाओं के नुकसान के क्षतिपूर्ति के लिए नुकसान जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले शामिल हो सकते हैं यानी चोट के कारण दावेदार चलने दौड़ने या बैठने में सक्षम नहीं हो सकता है, (iii) जीवन की उम्मीद के हानि के लिए क्षतिपूर्ति, यानी, चोट के कारण संबंधित व्यक्ति की सामान्य दीर्घायु है संक्षिप्त में है (iv)जीवन में असुविधा, कठिनाई, बेचैनी, निराशा, हताशा"

यह भी कहा गया कि जब भी किसी न्यायाधिकरण या अदालत को दुर्घटना के मामलों में मुआवजे की राशि तय करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें कुछ रद्द करने का काम, कुछ काल्पनिक विचार, कुछ विकलांगता की प्रकृति से जुड़ी कुछ सहानुभूति शामिल होती है। हालाँकि ऐसे सभी तत्वों को वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ देखा जाना की आवश्यकता है। क्षति का आकलन करते समय, अदालत अपनी राय को केवल अटकलों या कल्पना पर आधारित नहीं कर सकती है, हालांकि कुछ हद तक या अपरिहार्य अनुमान लगा सकती है।

तत्काल मामले में, अपीलार्थी को चिकित्सा देखभाल पर खर्च के रुप में 94,037 रुपया विशेष आहार के लिए 20,000 रुपया और उपचार के दौरान परिचारक के लिए खर्च के रुप में सम्मानित किया गया है। उसकी रीढ़ की हड्डी को लगी चोट और क्षति के कारण उसके स्थायी रूप से विकलांग और लकवाग्रस्त होने के लिए, अपीलार्थी, जिसे स्वीकार किया गया है कि स्थायी रूप से अक्षम रखा गया है, जिसको को केवल रु1,00,000 दिए गए है। हमारी राय है कि अपीलार्थी ने के समय अपने पिता के साथ काम करते हुए प्रति माह 2,000 रुपये की अपनी आय का दावा करने में सही था, और अगर हम 16 का गुणक भी लागू करते हैं, वह निराशा, हताशा और मानसिक तनाव के अलावा जीवन की उम्मीदों की हानि के कारण 3,84,000 रुपया के दावे का हकदार है खासकर उसके शेष जीवन में अपनी देखभाल के लिए एक स्थायी परिचारक रखना पड़ता है। इस राशि को 1,14,000 रुपये की राशि में जोड़ें। जिसके लिए अपीलार्थी को चिकित्सा देखभाल पर किए गए खर्च और उपचार की अवधि के दौरान होने वाली पीड़ा के लिए उचित रूप से हकदार ठहराया गया है, अपीलार्थी कुल 4,98,000 रुपये की राशि का हकदार है जिसे हम 5,00,000 रुपये तक को जोड़ मुकदमे की लागत सहित जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि। उपरोक्त राशि प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रदत्त 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 5,00,000 रुपये मुआवजे का हकदार मानते हुए अपीलीय आदेश को संशोधित कर के इस अपील की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

आर.के.एस अपील की अनुमति दी गई।

उपेंद्र नारायण सिंह